भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 255*
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाएं

*255. श्री के. गोपीनाथ:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार की तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चरण-11 के निष्पादन के लिए 63,000 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं और उक्त परियोजना के लिए अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“तमिलनाडु में मेट्रो रेल परियोजनाएं” विषय पर 12 दिसंबर 2024 के लिए श्री के. गोपीनाथ द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 255* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, राज्य का विषय है। इसलिए, मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को शुरू करना और विकसित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (यूटी) की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु सरकार के प्रस्तावों के आधार पर, चरण-I/विस्तार और चरण-II के तहत चेन्नई के लिए 85,395 करोड़ रुपये की लागत और 173 किलोमीटर की रूट लंबाई वाली मेट्रो परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त में से, वर्तमान में, चरण-I और चरण-I विस्तार के तहत शामिल 54 किमी मेट्रो नेटवर्क पहले से ही चालू है। तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट फरवरी 2024 में प्रस्तुत की है, हालांकि, व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर), जो मूल्यांकन प्रक्रिया की पूर्वापेक्षा है, दिनांक 05.12.2024 को ही प्रस्तुत की गई है। मेट्रो परियोजना की लागत अधिक होने के कारण इसके अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर विस्तृत जांच और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसी परियोजना का अनुमोदन प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार द्वारा 63,246 करोड़ रुपये की लागत पर चेन्नई मेट्रो चरण II परियोजना को स्वीकृति दी गई है। मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय निधियां परियोजना को कार्यान्वित करने वाले संबंधित विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं और स्वीकृति आदेश में उल्लिखित अपेक्षित शर्तों की पूर्ति के आधार पर जारी की जाती हैं। परियोजना को कार्यान्वित करने वाले चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड नामक एसपीवी ने परियोजना के लिए केंद्रीय वित्त सहायता की कोई मांग नहीं की है।